

वशिव प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022

प्रलिस के लयः

वशिव प्रेस स्वतंत्रता दवऱस, वशिव प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022

मेन्स के लयः

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और संबधति मुद्दे

चरचा में क्यौं?

3 मई, 2022 को [वशिव प्रेस स्वतंत्रता दवऱस](#) (WPFDF) के अवसर पर 'रपिर्टरस वदऱउट बॉर्डर्स' (RSF) द्वारा [वशिव प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक](#) का 20वाँ संस्करण प्रकाशति कयऱ गयऱ ।

- 180 देशों में भारत 150वें स्थान पर है ।

वशिव प्रेस स्वतंत्रता दवऱस:

- **परचयः**
 - वरष 1991 में [यूनेस्को](#) की जनरल कॉन्फरेंस की सफऱरशऱ के बाद वरष 1993 में संयुक्त राषट्र महासभा ने वशिव प्रेस स्वतंत्रता दवऱस की घोषणा की थी ।
 - यह दवऱस वरष 1991 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई 'वडिहोक' (Windhoek) उद्घोषणा को भी चहिनति करता है ।
 - वरष 1991 की 'वडिहोक घोषणा' एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के वकऱस से संबधति है ।
- **वशिव प्रेस स्वतंत्रता दवऱस 2022 की थीम:**
 - जर्नलऱज्म अंडर डजिटल सीज (Journalism under digital siege) ।

वशिव प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक:

- **परचयः**
 - यह वरष 2002 से 'रपिर्टरस सेन्स फ्रंटियर्स' (RSF) या 'रपिर्टरस वदऱउट बॉर्डर्स' द्वारा प्रत्येक वरष प्रकाशति कयऱ जऱता है ।
 - पेरसि में स्थति RSF **संयुक्त राषट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परषिद और फ्रैंकोफोनी** के अंतरराषट्रीय संगठन (OIF) के परामर्शी स्थतऱके साथ एक **स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठन** है ।
 - OIF, 54 फ्रेंच भाषी राषट्रों का एक समूह है ।
 - पत्रकारों के लयऱ उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार यह सूचकांक देशों और कषेत्रों को रैंक प्रदान करता है । हालाँकऱ यह पत्रकारति की गुणवत्ता का संकेतक नहीं है ।
- **स्कोरगऱ मानदंड:**
 - सूचकांक की रैंकगऱ **0 से 100 तक के स्कोर पर आधऱरति** होती है जो प्रत्येक देश या कषेत्र को प्रदान की जऱती है, जसिमें **100 सरवशुरेशठ संभव स्कोर** (प्रेस स्वतंत्रता का उच्चतम संभव स्तर) और **0 सबसे खराब स्तर** को प्रदर्शति करता है ।
- **मूल्यांकन मानदंड:**
 - प्रत्येक देश या कषेत्र के स्कोर का मूल्यांकन **पाँच प्रासंगकि संकेतकों** का उपयोग करके कयऱ जऱता है, जनिमें राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढँचा, आर्थकि संदर्भ, सामाजकि-सांस्कृतकि संदर्भ और सुरकषा शामिल हैं ।

वशिव के प्रदर्शन की मुख्य वशेषताएँ:

- **परचयः**

- रपिर्ट से पता चलता है कि "ध्रुवीकरण" में दोगुना वृद्धि हुई है, जो सूचना की अराजकता के कारण बढ़ी है, अर्थात् मीडिया ध्रुवीकरण देशों के भीतर व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के वभाजन को बढ़ावा देता है।

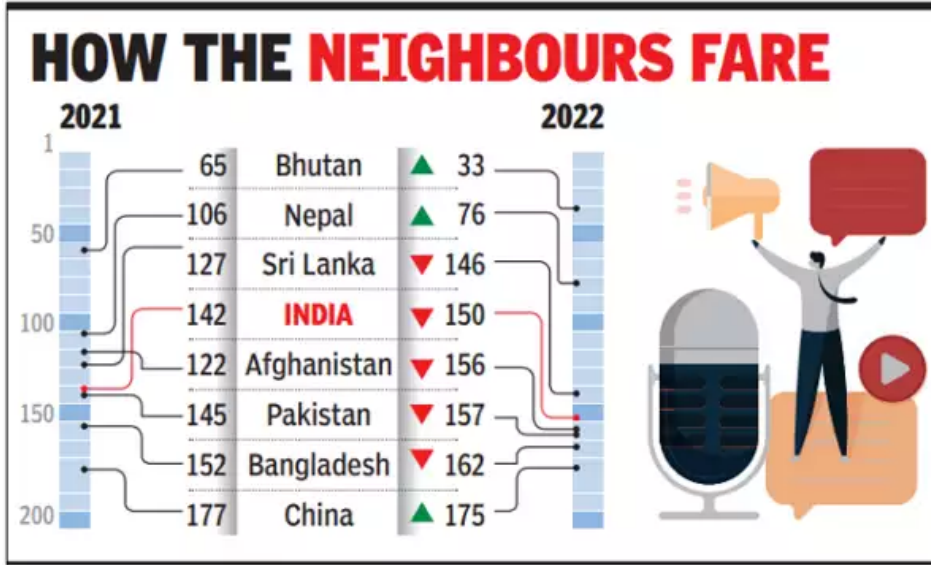
■ देशों की रैंकगि:

- शीर्ष और सबसे खराब प्रदर्शनकर्त्ता:

- नॉर्वे (प्रथम) डेनमार्क (दूसरा), स्वीडन (तीसरा), एस्टोनिया (चौथा) और फनिलैंड (पाँचवाँ) ने शीर्ष स्थान हासिल किया है।
- उत्तर कोरिया 180 देशों की सूची में सबसे नीचे रहा।
- रूस को 155वें स्थान पर रखा गया है।

- भारत के पड़ोसी:

- नेपाल वैश्विक रैंकगि में 30 अंकों की बढ़त के साथ 76वें स्थान पर पहुँच गया है।
- सूचकांक ने पाकस्तान को 157वें, श्रीलंका को 146वें, बांग्लादेश को 162वें और म्यांमार को 176वें स्थान पर रखा है।
- चीन 175वें स्थान पर है।



भारत का प्रदर्शन:

■ परचिय:

- भारत 2022 में 180 देशों में 142वें में से आठ पायदान गरिकर 150वें स्थान पर आ गया है।
- भारत 2016 के सूचकांक में 133वें स्थान पर था इसके बाद से उसकी रैंकगि में लगातार गरिवाट आ रही है।
- रैंकगि में गरिवाट के पीछे का कारण "पत्रकारों के खलिफ हसिा" और "राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया" में वृद्धि होना है।

■ भारत की रैंकगि में गरिवाट के कारण:

- सरकार का दबाव :

- सूचकांक के अनुसार, भारत में मीडिया लोकतांत्रिक रूप से प्रतष्ठिति राष्ट्रों की तुलना में "तेज़ी से सत्तावादी और/या राष्ट्रवादी सरकारों" के दबाव का सामना कर रहा है।

- नीतगित ढाँचे में दोष:

- यद्यपि नीतगित ढाँचा सैद्धांतिक रूप से सुरक्षात्मक है, यह मानहानि, राजद्रोह, नयायालय की अवमानना और सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खलिफ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए उन्हें "राष्ट्र-वसिधी" करार देता है।

- मीडियाकर्मियों के लयि भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश:

- रपिर्ट के मुताबकि, भारत मीडियाकर्मियों के लयि भी दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है।
 - पत्रकारों को पुलसि हसिा, राजनीतिक कार्ककर्त्ताओं द्वारा घात लगाकर हमला करने और आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा घातक प्रतशोध सहति सभी प्रकार की शारीरिक हसिा का सामना करना पड़ता है।

- कश्मीर मुद्दा:

- कश्मीर में स्थिति "चतिजनक" बनी हुई है और पत्रकारों को अक्सर पुलसि तथा अर्द्धसैनिक बलों द्वारा परेशान किया जाता है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता:

- संवधान देश का सर्वोच्च कानून है, जो अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो 'भाषण की स्वतंत्रता आदिके संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण' से संबंधित है।

- प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (A) के तहत संरक्षित है, जिसके अनुसार "सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा"।
- रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है।
- हालाँकि प्रेस की स्वतंत्रता भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत इस पर कुछ प्रतिबंधों को आरोपित किया गया है, जो इस प्रकार हैं-
 - भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिये उकसाना।

स्रोत: द हट्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/world-press-freedom-index-2022>

